NHRC pulls up J'khand govt for failing to compensate Silicosis patients

Debashish Sarkar

letters@hindustantimes.com

JAMSHEDPUR: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a final warning to the Jharkhand Government for its continued failure to comply with directions regarding compensation to silicosis-affected workers in Musaboni, East Singhbhum, people involved with the matter said on Friday.

The Commission has given the Chief Secretary four weeks to submit a compliance report, failing which coercive action will be invoked.

The Commission has perused the record. Let the Jharkhand chief secretary be given last opportunity to submit the requisite report in the matter within four weeks (latest by July 25, 2026), failing which the Commission shall be constrained to invoke it's coercive powers, under section 13 of the Protection of Human Rights Act-1993 for physical appearance of the authority concerned," the NHRC letter to the state chief secretary read.

"The Commission noted that the Chief Secretary's additional report clarifying the status of 27 workers has still not been received. Earlier directions (April 2024) for a detailed report has also not been complied with. Meanwhile, the complainant approached the Commission again (April 2025), calling the State's inaction "willful defiance of NHRC authority" and "violation of the right to life" under Article 21 of the Constitution," the NHRC has observed in its letter post it's meeting on June 17 last.

The case, pending since 2007 (Case No. 1013/34/6/07-08), involves workers of

Ramming Mass (quartz crushing) industries who developed silicosis—a fatal occupational lung disease—due to prolonged exposure to silica dust.

"In 2014, the NHRC had directed the Jharkhand Government to pay Rs 4 lakh each to the next of kin of 24 deceased workers, provide medical cards to 27 identified victims, and offer employment under MNREGA. The state government, however, has not complied with the NHRC order completely as on date. The NHRC has given the state chief secretary to file a comprehensive and complete compliance report by July 25," Samit Carr, the complainant and secretary general of Occupational Safety & Health Association of Jharkhand (OSHAJ), told HT on Friday..

Samit Carr, on behalf of OSHAJ, has raised serious concerns like deliberate denial by the East Singhbhum district administration despite the 27 workers being identified as silicosis-affected in a 2014 medical camp,.

THE COMMISSION HAS GIVEN THE CHIEF SECRETARY FOUR WEEKS TO SUBMIT A COMPLIANCE REPORT

"The district deputy commissioner's (DC's) office is demanding fresh medical records, effectively delaying compensation. Government doctors at Mahatma Gandhi Memorial Medical College Hospital (MGMMCH), Jamshedpur, are issuing conflicting diagnoses. Workers previously diagnosed with silicosis through ILO Rating by expert doctors are being declared "normal" or suffering from "TB" (tuberculosis) in later reports," NHRC has stated, quoting Carr's complaint.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Amar Ujala City, Noida, 20/06/2026

Page No: 4, Size: 20.80cm × 6.27cm

नाबालिग को जेल में रखने पर डीजीपी व डीजी जेल को मिला नोटिस

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। श्रमिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 16 वर्षीय किशोर को बालिग दर्शाकर लुक्सर जिला जेल भेजने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है।

आयोग ने इसे मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और महानिदेशक कारागार (डीजी जेल) को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया

एनएचआरसी ने मामले की स्वतंत्र जांच के लिए अपने महानिदेशक को विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश भी दिया है। आयोग ने एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नाबालिग को वयस्क कैदियों के बीच रखने की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।

जानकारी के अनुसार फेज-2 थाना पुलिस ने 14 अप्रैल 2026 को श्रमिक आंदोलन से जुड़े मामले में एक किशोर को गिरफ्तार किया था। पुलिस दस्तावेजों में उसे बालिग दर्शाते हुए लुक्सर जेल भेज दिया था। बाद में न्यायालय परिसर में हथकड़ी लगे किशोर को देखकर एक अधिवक्ता को उसकी उम्र पर संदेह हुआ। पूछताछ में किशोर ने स्वयं को नाबालिग बताया।

इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनसे उसकी उम्र 16 वर्ष साबित हुई। दस्तावेजों की जांच के बाद अदालत ने 8 जून को उसे वयस्क जेल से हटाकर बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। भंगेल निवासी किशोर एक परचून की दुकान पर काम करता है। आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद बृहस्पतिवार को किशोर को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया।

Dainik Bhaskar, Muzaffarpur, 20/06/2026

Page No: 3, Size: 19.82cm × 11.96cm

असुरक्षित बचपन : राज्य में हर 36 मिनट पर गुम हो रहा एक बच्चा, लगातार दूसरे साल मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर

मासूमों पर मंडराता खतरा... एक साल में मुजफ्फरपुर में 890 बेटियों समेत 1050 बच्चे लापता, मानव तस्करी की आशंका

क्राइमरिपोर्टर | मुजफ्फरपुर

बिहार में औसतन हर 36 मिनट पर एक बच्चा लापता हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से लेकर बाल अधिकार संगठनों तक ने इस बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता जताई है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में बिहार से 14,699 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें 7,772 बच्चों को बरामद कर लिया गया, जबकि 6,927 बच्चे अब भी लापता हैं। यानी लगभग हर दूसरा परिवार अपने बच्चे की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। राज्य में हर महीने करीब 1,225 और प्रतिदिन लगभग 40 बच्चे गायब हो रहे हैं। गुमशुदा बच्चों में लड़कियों की संख्या अत्यधिक है। वर्ष 2025 में लापता हुए 14,699 बच्चों में 12,526 लड़कियां और केवल 2,173 लड़के शामिल हैं। यानी गायब हुए बच्चों में 85.2 फीसदी लड़कियां हैं। पुलिस अधिकारियों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में किशोरियों और लड़कियों की गुमशुदगी के पीछे संगठित मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग), जबरन बाल विवाह, घरेलू श्रम और यौन शोषण जैसे बड़े और खतरनाक रैकेट सक्रिय हैं। बीचे दो साल से राजधानी पटना व मुजफ्फरपुर में स्थिति भयावह बनी हुई है। दोनों जिले बेटियों के गायब होने के मामले में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वर्ष 2025 में जहां पटना से 1080 किशोरियों समेत 1305 बच्चे गायब हुए। वहीं, मुजफ्फरपुर में 890 किशोरियों समेत 1050 बच्चे लापता हो गए।

बच्चों को गायब करने में मानव तस्कर, बाल श्रम, यौन शोषण करने वाले गिरोह सक्रिय

जांच एजेंसियों के अनुसार कई बच्चों को बिहार से बाहर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक ले जाया जाता है। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में भी ऐसे मामलों की आशंका बनी रहती है। बच्चों को ईंट-भट्ठों, कारखानों, घरेलू कामकाज, भिक्षावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेले जाने का खतरा बना रहता है।

चिंता की बात : दो वर्षों में बच्चों के गायब होने के मामले में 20 फीसदी की वृद्धि दर्ज

राज्य में बीते दो वर्षों में बच्चों के गायब होने के मामले में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में बिहार में 12,299 बच्चे लापता दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 14,699 पहुंच गई। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए इस वर्ष मार्च में एनएचआरसी ने बिहार सहित पांच राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और संभावित मानव तस्करी नेटवर्क पर चिंता जताई है।

वर्ष 2025 में बच्चों के गायब होने के मामले में राज्य के टॉप-5 जिले

जिला	लड़के	लड़कियां	कुल बच्चे
पटना	225	1,080	1,305
मुजफ्फरपुर	160	890	1,050
पूर्वी चंपारण	120	780	900
गया	115	695	810
पूर्णिया	102	640	742

वर्ष 2024 में बच्चों के गायब होने के मामले में राज्य के टॉप-5 जिले

जिला	लड़के	लड़कियां	कुल बच्चे
पटना	210	950	1,160
मुजफ्फरपुर	145	780	925
गया	110	620	730
पूर्णिया	95	580	675
कटिहार	88	540	628

प्रदेश में हर 36 मिनट में गायब हो रहा एक बच्चा

वर्ष 2025 में विभिन्न जिलों से 14,699 बच्चे लापता, पुलिस व अन्य एजेंसियों ने 7,772 को किया बरामद

शुभम कुमार • जागरण

पटना : प्रदेश में बच्चों की गुमशुदगी अब केवल पुलिस रिकार्ड का एक शुष्क आंकड़ा नहीं रह गई है। यह एक ऐसा गहराता मानवीय संकट बन चुका है, जिसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से लेकर बाल संरक्षण संगठनों तक को हिलाकर रख दिया है। वर्ष 2025 में राज्यभर से 14,699 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने 7,772 बच्चों को बरामद कर लिया, लेकिन 6,927 अब भी लापता हैं। आज भी हर दूसरे बच्चे की तलाश जारी है और उनके माता-पिता का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। वर्ष 2025 के इन आंकड़ों का समय के आधार पर विश्लेषण किया जाए, तो स्थिति बेहद डरावनी नजर आती है। राज्य में हर महीने औसतन 1,225 बच्चे लापता हो रहे हैं। इसका औसत निकाला जाए तो यह संख्या 41 बच्चे प्रतिदिन बैठती है। यानी हर घंटे औसतन 1.70 बच्चे और हर 36 मिनट में एक बच्चा अपने घर-परिवार से दूर हो जा रहा है।

4 महीनों में स्वत: एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पास चला जाता गुमशुदगी का मामला

44 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाइयां भी प्रदेश में सक्रिय

3 एयरपोर्ट पटना, गया और दरभंगा पर विशेष निगरानी इकाइयां बच्चों पर रखती हैं नजर

बिहार में नाबालिग के लापता होने की संख्या बढ़ी है। हमलोग आयोग के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें पुलिस को आगे आने की जरूरत है। लापता बच्चों को खोजने के लिए पुलिस को सक्रिय होना होगा। जांच में एक नया गिरोह सामने आया, जो नाबालिग को बहला-फुसला कर आर्केस्ट्रा के दलदल में धकेल रहा है। पुलिस अगर लापता बच्चे-बच्चियों को ट्रैक करे तो बड़े-बड़े गिरोह को पकड़ा जा सकता है। हमलोगों को जब जानकारी मिलती है पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस के सहयोग से कई लापता बच्चे-बच्चियों को बरामद भी किया गया है।

– **राकेश कुमार सिंह**, सदस्य, बिहार कमीशन फोर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स।

एनएचआरसी के अनुसार, राज्य में 2013 से लगातार हर साल 12 हजार से 14 हजार लोगों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नाबालिग का है। इसको गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2026 में बिहार समेत पांच राज्यों से विशेष रिपोर्ट तलब की है। यह इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की लगभग 36 प्रतिशत आबादी 15 वर्ष से कम उम्र की है, जिससे बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ी आबादी को सीधे प्रभावित करता है। इसी सर्वे (एनएफएचएस-5) के अनुसार, बिहार में 20-24 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 41 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले ही हो चुका था।

लापता बच्चों में 85 प्रतिशत बेटियां: सबसे चौंकाने वाला पहलू लड़कियों की संख्या है। कुल 14,699 लापता बच्चों में 12,526 केवल लड़कियां हैं, जबकि लड़कों की संख्या 2,173 है। यानी लापता होने वाले बच्चों में 85.2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेटियों की है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, लड़कियों के गायब होने की रफ्तार लड़कों की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया कि किशोरियों की इतनी बड़ी संख्या में गुमशुदगी के पीछे बाल विवाह, जबरन विवाह, प्रेम प्रसंग, घरेलू काम के लिए शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर संगठित अपराध शामिल हैं।

दो साल में 20 प्रतिशत बढ़ा संकट देश के टाप राज्यों में बिहार: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में 12,299 बच्चे लापता हुए थे। अब एनएचआरसी के अनुसार, वर्ष 2025 में संख्या 14,699 पर पहुंच गई। यानी मात्र दो वर्षों में लापता बच्चों के मामलों में 2,400 की वृद्धि हुई, जो 19.5 प्रतिशत उछाल है। प्रदेश में 44 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाइयां हैं। चार महीनों में स्वतः एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पास गुमशुदगी का मामला चला जाता है। उसके बाद जांच होती है। पुलिस से भी पूरी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसके साथ ही पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी इकाइयां भी हैं, जो बच्चों पर नजर रखती हैं।

Source: https://www.thehansindia.com/amp/news/national/odisha-cm-majhi-suspends-ips-officer-and-home-dept-osd-1087887

Odisha CM Majhi suspends IPS officer and Home dept OSD
The Hans IndiaUpdate: 2026-06-19 12:26 IST

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has suspended senior IPS officer Dayal Gangwar, who is currently serving as Officer on Special Duty (OSD) in the state Home Department, according to the Chief Minister's Office.

Although the state government on Thursday has not yet disclosed the reason behind the disciplinary action against the Additional Director General of Police (ADGP)-rank officer, it is suspected that the move is linked to Gangwar's alleged involvement in the mental harassment of former Government Railway Police (GRP) Constable Soumya Ranjan Swain, who was lynched by a mob in the Balianta area on the outskirts of Bhubaneswar last month.

The disciplinary action reportedly follows a probe carried out by Arun Bothra, a senior IPS officer and ADGP Railways and Coastal Security.

On May 7, Soumya, a Railway Constable, was beaten to death by a mob of villagers over allegations of sexually assaulting a girl in the Balianta area on the outskirts of Bhubaneswar.

Meanwhile, Soumya's aggrieved mother levelled serious allegations against Gangwar, claiming that her son had been under severe mental pressure due to the 1998-batch IPS officer, during Gangwar's posting as ADGP Railways.

She also alleged that the senior police officer not only assigned personal work to the deceased Constable but also subjected him to mental harassment.

According to Soumya’s mother, the former GRP Constable was looking after a gym centre allegedly owned by one associate of Gangwar in Bhubaneswar.

As the controversy escalated, the state government on May 25 transferred Gangwar, then serving as ADGP Communication and posted him as OSD in the Home Department.

Later, following the intervention of the National Human Rights Commission, the ADGP (Railways and Coastal Security) was directed to investigate the allegations against Gangwar and submit a report in this regard.

The Crime Branch of Odisha Police, which is investigating the brutal mob lynching of Soumya, has so far arrested 18 accused persons, while a search is underway to nab several others who are still scot-free.

Source: https://www.thedailyjagran.com/india/one-child-goes-missing-every-36-minutes-in-bihar-data-reveals-14699-disappeared-in-2025-85-percent-were-girls-10317135

One Child Goes Missing Every 36 Minutes In Bihar: Data Reveals 14,699 Disappeared In 2025, 85% Were Girls

Bihar is grappling with a severe missing children crisis, with a child vanishing every 36 minutes and 14,699 cases reported in 2025, 85 per cent of whom are girls. The National Human Rights Commission is urging stronger intervention as human trafficking, particularly through Patna, remains a significant concern.
By Chetna Shree Fri, 19 Jun 2026 07:29 PM (IST) Source:JND

Shubham Kumar, Patna: The rising number of missing children cases in Bihar has escalated from a tracking issue in local police records to a humanitarian crisis. The trend has drawn significant attention from the National Human Rights Commission (NHRC) and several child protection organisations, who are now pressing for more effective intervention and accountability from state authorities.

14,699 Children Were Reported Missing In 2025
According to a report by Jagran.com, a total of 14,699 children were reported missing from Bihar in 2025. While authorities recovered 7,772 of those children, 6,927 individuals remain missing. This gap means that every second family is still waiting for their children to return home.

A Child Goes Missing Every 36 Minutes
Data from 2025 shows that an average of 1,225 children were reported missing every month in Bihar, translating to approximately 40 children per day. This means a child goes missing every 36 minutes, making it highly probable that a new case is reported by the time it takes for anyone to finish reading this report.

Nearly 12,000-14,000 People Reported Missing Every Year Since 2013
According to the National Human Rights Commission (NHRC), 12,000 to 14,000 people have been reported missing in Bihar every year since 2013. Data shows that minor children account for a significant portion of these ongoing cases.

In response, the NHRC has sought special reports from Bihar and four other states.

85% Of Missing Children Are Girls
The most disturbing fact is that girls constitute a disproportionately large proportion of missing children. Of the 14,699 children reported missing in 2025, 12,526 were girls and 2,173 boys, meaning girls account for 85.2 per cent of all cases.

Police headquarters data indicate that the rate for girls going missing is nearly six times higher than that of boys.

An Increase Of 2,400 Cases In Just Two Years
According to data from the National Crime Records Bureau (NCRB), missing children cases in Bihar rose from 12,299 in 2023 to 14,699 in 2025. The increase of 2,400 cases represents a 19.5 per cent increase, nearly 20 per

cent in just two years.

Under the SOP of the Bihar Police, if a missing child is not found within four months, the case is automatically transferred to the Anti-Human Trafficking Unit (AHTU). While the state has 44 AHTUs, three airport surveillance units, special juvenile police units, and the Mission Vatsalya portal, recovery rates remain unsatisfactory.

Bihar Among Top Affected States

Bihar is among the top states in the country affected by missing children, alongside West Bengal and Madhya Pradesh. Experts believe that a large population, poverty, migration and challenges of border areas make this crisis more serious.

Patna - A Major Transit Hub For Human Traffickers

According to the report, the state's capital, Patna, is a major transit hub for human traffickers due to its extensive rail, road, and air connectivity. Police and child protection organisations identify Patna Junction, Rajendra Nagar Terminal, Danapur, Gardanibagh, Kankarbagh, Phulwari Sharif, and Patna City as the most vulnerable areas.

What Investigation Revealed?

According to investigating agencies, missing children from Bihar were taken to Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and areas bordering Nepal. These children are forced into networks of brick kilns, factories, domestic work, begging, forced marriage and sexual exploitation.

The Railway Protection Force's 'Operation Nanhe Farishte' rescued over 20,000 children in 2023 and more than 25,000 children in 2024, with a significant number of children from Bihar.

Source: https://www.siasat.com/allu-arjun-to-appear-in-hyderabad-court-in-pushpa-2-stampede-case-3492231/

Siasat.com/News/Hyderabad/Pushpa 2 stampede case: Allu Arjun to appear in Hyderabad court

Pushpa 2 stampede case: Allu Arjun to appear in Hyderabad court

The incident at Sandhya Theatre claimed the life of Revathi, 39, while her son Sritej sustained critical injuries.
News Desk Published: 19th June 2026 1:58 pm IST| Updated: 19th June 2026 3:25 pm IST

Hyderabad: A Hyderabad court on Friday, June 19, issued notices to actor Allu Arjun, directing him to appear in person on June 22 in connection with the Sandhya Theatre stampede case in which a woman lost her life during the premiere of his film Pushpa 2.

The Nampally Court also issued summons to 19 other accused in the case, which has a total of 23 chargesheeted persons, including the theatre's owners and partners, their staff, Allu Arjun's manager and other event personnel.

Allu Arjun has been named accused no 11 in the case stemming from the stampede at Sandhya Theatre on December 4, 2024, when massive crowds gathered for the premiere of "Pushpa 2: The Rule."

Woman dead in stampede
The incident at Sandhya Theatre at RTC X road claimed the life of Revathi, 39, while her son Sritej sustained critical injuries. She, her husband Bhaskar, and their two children had gone to the screening because Sritej was an ardent fan of Allu Arjun, an outing that turned into devastation.

The actor, who was present at the theatre at the time of the incident, was booked along with his team and the theatre management for culpable homicide not amounting to murder.

Lapses in crowd management: Police
Hyderabad Police Commissioner VC Sajjanar had said the investigation established lapses in planning, crowd management, security arrangements and coordination among the theatre management, event organisers and private security personnel. The chargesheet was filed before the court on December 24, 2025, with 14 of the accused having been arrested and nine others, who obtained anticipatory bail, served notices.

The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier expressed dissatisfaction with the police report on the incident, saying the police machinery appeared negligent in providing adequate security despite the size of the crowd.

Source: https://www.prameyanews.com/soumya-swain-mob-lynching-case-parents-demand-dismissal-of-suspended-ips-officer-seek-cbi-probe

Soumya Swain mob lynching case: Parents demand dismissal of suspended IPS Officer, seek CBI probe

A day after senior IPS officer Dayal Gangwar was suspended in connection with the alleged mob lynching of GRP constable Soumya Ranjan Swain, the deceased constable's parents demanded his dismissal from service and sought a CBI investigation into the case
Published By : Bratati Baral | June 19, 2026 1:05 PM

Bhubaneswar, June 19: A day after senior IPS officer Dayal Gangwar was suspended in connection with the alleged mob lynching of GRP constable Soumya Ranjan Swain, the deceased constable's parents demanded his dismissal from service and sought a CBI investigation into the case.

Speaking to the media, Soumya's father Dushasan Swain said mere suspension was not enough punishment. "What is the benefit of suspending him? After a few months, he may return to duty and continue receiving salary. He should be dismissed from service and sent to jail," he said.

While thanking Chief Minister Mohan Charan Majhi for taking the matter seriously, Dushasan reiterated the family's demand for a CBI probe, claiming there was a larger conspiracy behind his son's death. "We have been demanding a CBI investigation since the incident occurred. We are not satisfied with the Crime Branch probe and request the Chief Minister to support our demand," he added.

Allegations had earlier surfaced that Soumya was forced to perform personal errands at Gangwar's residence and was subjected to harassment. Following the controversy, Gangwar was first shifted as Officer on Special Duty (OSD) in the Home Department on May 25 before being placed under suspension.

The case also reached the National Human Rights Commission (NHRC), which directed a two-member team to conduct an inquiry. The team visited Bhubaneswar and carried out a five-day investigation, including a probe into the harassment allegations at the office of the Railway SP. Subsequently, ADG Arun Bothra conducted a separate inquiry and submitted a report to DGP Y.B. Khurania.

Soumya's mother, Kabita Swain, expressed dissatisfaction over the suspension and demanded stricter action. "My son was brutally murdered as part of a planned conspiracy. Those who assaulted him and those who remained silent spectators should face the harshest punishment," she said, reiterating the family's demand for a CBI investigation.

Meanwhile, the Crime Branch has intensified its probe. On June 7, a team led by DSP Narendra Behera visited a gym associated with Soumya at Adashpur and questioned its officials. Investigators examined documents, collected records and reviewed CCTV footage as part of the ongoing investigation.

The Crime Branch team also met Soumya's mother and collected a diary maintained by the deceased constable, along with several personal belongings, which are expected to aid the investigation.

Source: https://www.northblocksouthblock.com/senior-top-cop-suspended-amid-sr-swain-death-investigation/

Bureaucracy

Senior Top Cop Suspended Amid SR Swain Death Investigation
Parijat Tripathi
Last updated: June 20, 2026 7:52 am

Who Is IPS Officer Dayal Gangwar? Odisha Government Suspends Senior Cop Amid Soumya Ranjan Swain Death Controversy

Senior Odisha cadre IPS officer Dayal Gangwar has been suspended in connection with the death of GRP constable Soumya Ranjan Swain. Here is a detailed look at Gangwar's career, key postings, awards, the allegations against him and the ongoing Crime Branch and NHRC investigations.

Senior Indian Police Service (IPS) officer Dayal Gangwar has found himself at the centre of one of Odisha's most closely watched controversies after the state government ordered his suspension in connection with the death of Government Railway Police (GRP) constable Soumya Ranjan Swain.

The suspension, approved by Chief Minister Mohan Charan Majhi, marks a major turning point in a case that has generated widespread public attention, sparked political debate and prompted investigations by multiple agencies, including the Odisha Crime Branch and the National Human Rights Commission (NHRC).

The controversy revolves around allegations that the senior police officer subjected the deceased constable to mental harassment and required him to perform personal and domestic duties unrelated to official police work. While the allegations are still under investigation, the government's decision to suspend a senior IPS officer reflects the seriousness with which the matter is being treated.

As the probe gathers pace, attention has increasingly shifted towards understanding who Dayal Gangwar is, his long career in policing, the positions he has held and the circumstances that led to his suspension.

A Senior IPS Officer with Nearly Three Decades of Service

Dayal Gangwar belongs to the 1998 batch of the Indian Police Service and is an officer of the Odisha cadre.

Originally from Uttar Pradesh, Gangwar has spent almost three decades in policing and public service, holding a wide range of assignments in both Odisha and the Central Government.

Over the years, he built a reputation as an experienced police administrator and rose steadily through the ranks to become one of the senior-most officers in the Odisha Police hierarchy.

His career has included responsibilities in policing, security management, modernization initiatives, communications systems and administrative leadership.

Until recently, he was serving in senior leadership positions within Odisha Police and was regarded as an influential officer with extensive operational and administrative experience.

Educational Background and Early Life

Gangwar's educational journey began in Odisha, where he completed his schooling at IMST English Medium Nursery and High School in Malkangiri.

He later secured admission to the prestigious St. Stephen's College, University of Delhi, one of India's most respected higher educational institutions.

At St. Stephen's, he pursued a Bachelor of Arts (Honours) degree before preparing for the highly competitive Union Public Service Commission (UPSC) Civil Services Examination.

After successfully clearing the examination, he joined the Indian Police Service and was allotted the Odisha cadre as a direct recruit officer.

Like many IPS officers of his generation, Gangwar began his career at the district level, gaining practical exposure to law enforcement, public order management and policing administration before moving into more senior assignments.

Recognition and Awards

Throughout his career, Gangwar received recognition for his service within the police force.

He was awarded the Police Medal for Meritorious Service in both 2014 and 2015, honours that reflected his contributions to policing and public administration.

Such awards are typically granted to officers who demonstrate dedication, professional competence and distinguished service over an extended period.

The recognition helped strengthen his standing within the police establishment and contributed to his progression into senior leadership positions.

Career Across State and Central Assignments

Over a span of nearly 28 years, Gangwar served in a variety of important assignments that exposed him to different aspects of policing and security management.

His experience was not limited to state policing alone. He also spent time on central deputation, where he handled responsibilities linked to national security infrastructure.

Central Deputation in CISF

One of the most significant phases of his career came between 2020 and 2023 when he served as Inspector General in the Central Industrial Security Force (CISF).

The CISF operates under the Ministry of Home Affairs and is responsible for protecting critical infrastructure, industrial establishments, airports and strategic assets across the country.

As Inspector General, Gangwar was involved in overseeing large-scale security operations and managing complex security arrangements.

The assignment provided him with valuable experience in national-level security administration and institutional management.

Return to Odisha Police

Following his tenure with the CISF, Gangwar returned to Odisha and was promoted to the rank of Additional Director General of Police (ADGP).

His return placed him among the state's senior police leadership, and he subsequently held several important positions.

Among the major assignments handled by him were:

- ADGP, Railways and Coastal Security
- ADGP (Headquarters), Odisha Police
- ADGP, Modernisation
- ADGP, Communications

These positions carried significant responsibility and placed him at the centre of several important policing and security initiatives undertaken by the state government.

His role in railway and coastal security was particularly important given Odisha's extensive coastline and expanding transportation network.

The Death of Constable Soumya Ranjan Swain

The controversy surrounding Gangwar emerged following the death of GRP constable Soumya Ranjan Swain.

According to reports, Swain died on May 7, 2026, following an incident in the Balianta area that reportedly stemmed from a traffic-related altercation and subsequently escalated into mob violence.

What initially appeared to be a tragic law-and-order incident soon developed into a larger controversy after allegations surfaced regarding the constable's working conditions and his relationship with senior officers.

Questions began to emerge about whether Swain had been performing duties outside the scope of his official responsibilities.

Family Raises Allegations of Harassment

The controversy intensified after Swain's parents publicly alleged that their son had been subjected to sustained mental pressure while serving under Gangwar.

According to the family, the constable was frequently assigned personal and domestic tasks that had little connection with his official duties as a Government Railway Police constable.

The allegations included claims that he was required to perform household chores, run personal errands and undertake assignments unrelated to policing responsibilities.

These accusations triggered widespread public debate and led to demands for an independent investigation.

The allegations also reignited broader concerns about the alleged misuse of subordinate personnel for personal work by senior officials.

Government Initiates Action

As public scrutiny increased, the Odisha government initiated inquiries into the matter.

Preliminary findings reportedly suggested that the constable may have been engaged in domestic and personal work without proper authorization or official orders.

Pending a fuller investigation, the government first removed Gangwar from his operational responsibilities and posted him as Officer on Special Duty (OSD) in the Home Department.

The transfer was widely viewed as an interim administrative measure while inquiries continued.

DGP Report Leads to Suspension

The situation took a more serious turn after reports emerged regarding a confidential inquiry conducted at the highest levels of the police establishment.

According to media reports, findings submitted by the Director General of Police raised additional concerns.

The inquiry reportedly found that eight Government Railway Police personnel continued to remain attached to Gangwar’s residence even after he had been transferred from his position as ADGP, Railways and Coastal Security.

These findings are believed to have played a significant role in the government’s decision to suspend him on June 18, 2026.

Crime Branch and NHRC Investigations Continue

The suspension does not conclude the matter.

The Odisha Crime Branch is currently conducting a detailed investigation into the allegations and the circumstances surrounding Swain’s death.

At the same time, the National Human Rights Commission has also taken note of aspects of the case, underscoring its wider public significance.

Investigators are expected to examine deployment records, official communications, witness testimonies, service documents and other evidence to determine whether departmental norms or legal provisions were violated.

A Case Being Closely Watched

The death of Soumya Ranjan Swain has evolved into one of the most sensitive and closely monitored cases in Odisha this year.

For the government, the case represents a test of accountability and transparency within the police system. For law enforcement agencies, it raises important questions about workplace conduct, supervision and the treatment of subordinate personnel.

With Dayal Gangwar now under suspension and multiple investigations underway, the focus remains firmly on establishing the facts surrounding the case.

The findings of the Crime Branch, departmental authorities and the NHRC will ultimately determine whether further disciplinary, administrative or legal action is warranted.

Until then, the case continues to attract significant public attention, with many awaiting answers regarding the circumstances that led to the death of constable Soumya Ranjan Swain and the allegations that have brought a

senior IPS officer’s long career under intense scrutiny.

Source: https://www.etvbharat.com/amp/en/state/odisha-constable-soumya-ranjan-swain-lynching-cm-majhi-suspends-senior-ips-officer-over-harassment-allegations-enn26061900989

ETV Bharat / state

Odisha Constable Lynching: CM Majhi Suspends Senior IPS Officer Over Harassment Allegations

Swain's family had alleged that he was subjected to both physical and mental harassment by Gangwar, who was then ADG, reports Satyajit Raut
By ETV Bharat English Team
Published : June 19, 2026 at 10:46 AM IST

Bhubaneswar: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi on Thursday suspended senior IPS officer Dayal Gangwar, who was embroiled in controversy over the lynching of GRP constable Soumya Ranjan Swain last month, a statement from the CMO said.

Gangwar, a 1998-batch police officer who was in charge of the OSD of the Home department, was suspended over allegations of harassment levelled by the family of Swain. Gangwar's name had surfaced during the investigation into the lynching of Swain, who was allegedly tied to a pole and beaten to death in Bhingarpur-Kaja in the Balianta Police Station area on May 7.

The mob attack took place after a woman accused the constable of attempting to rape her following a collision between his motorcycle and her two-wheeler, according to police. As the incident triggered a furore in the state, Swain's family had alleged that he was subjected to both physical and mental harassment by Gangwar, who was then ADG (Communication), and demanded that he be brought within the ambit of the investigation.

Kavita, Swain’s mother, had alleged that Gangwar used to torture her son by forcing him to do personal work. She also alleged that Soumya used to manage Gangwar's gym centre in Bhubaneswar. The IPS officer was subsequently transferred and posted as OSD in the Home Department by the state government.

Following this, ADG (Railways) Arun Bothra was directed to conduct an inquiry into allegations that Gangwar had subjected Swain to mental harassment by allegedly compelling him to perform personal and domestic chores unrelated to official duties.

Bothra was also tasked with examining whether the stress described in Swain's personal diary had any bearing on the circumstances leading to his death. The inquiry report was submitted to the DGP last month. A National Human Rights Commission team from New Delhi, which visited the state to inquire into the death, had also questioned Gangwar.

The opposition BJD had also raised questions over the alleged connection between the deceased constable and the senior IPS officer, who was ADG (Railways) two years back and supposedly knew Swain since then. The party claimed that Swain had been engaged in work at Gangwar's residence and gymnasium instead of performing official police duties.

As part of the probe into the mob-lynching case, the state government had earlier suspended four police personnel, disengaged two home guards and transferred the inspector-in-charge of Balianta police station over their alleged roles and conduct in the incident. Police have so far arrested 18 persons, including the prime accused, in connection with the lynching.

Source: https://pragnews.com/en/major-rescue-operation-frees-115-assam-youths-from-bihar-trafficking-ring

Regional
Major Rescue Operation Frees 115 Assam Youths from Bihar Trafficking Ring

A significant multi-agency operation today successfully rescued 115 boys and girls from Assam, many of them minors, who were trapped in a human trafficking racket in Bihar's Samastipur district. Nine individuals have been arrested in connection with the case.
Jun 19, 2026 2 mins read System Admin

In Short
A significant multi-agency operation today successfully rescued 115 boys and girls from Assam, many of them minors, who were trapped in a human trafficking racket in Bihar's Samastipur district
Nine individuals have been arrested in connection with the case
In a major breakthrough against human trafficking, 115 young individuals from Assam, including 48 girls and 67 boys, were rescued in the early hours of Wednesday from Samastipur district in Bihar. The extensive operation, spearheaded by Mission Mukti Foundation in collaboration with the Sashastra Seema Bal (SSB) and overseen by the National Human Rights Commission (NHRC), brought to light a sophisticated network preying on vulnerable youths from the northeastern state. Many of those freed are reportedly minors.

Following the rescue, law enforcement authorities have apprehended nine individuals believed to be key members of the trafficking ring. Investigations into the illicit operation have begun to unravel a deeply entrenched network that lured victims with false promises before subjecting them to exploitation far from their homes.

Reports indicate that traffickers specifically targeted economically disadvantaged families residing in regions along the India-Bhutan border, particularly in Assam’s Tamulpur district. Youths from areas such as Tamulpur, Bhairabkunda, and Dimakuchi in Udalguri district, as well as Biswanath Chariali, Doomdooma, and Mangaldai, were enticed with fraudulent offers of government jobs, often in the Agriculture Department. Victims were reportedly coerced into paying "employment fees" under these false pretenses.

Instead of legitimate employment, the rescued individuals were transported to Samastipur, Bihar, where they were confined within what appeared to be a fake call centre. Here, they were allegedly subjected to various forms of exploitation, including forced labour and coercion into dubious network marketing schemes, highlighting the deceptive and coercive tactics employed by the traffickers.

The successful operation underscores the persistent challenges of human trafficking in the region and the critical need for continued vigilance and inter-agency cooperation to dismantle such criminal enterprises. Further investigations are expected to reveal more details about the full extent of this cross-state racket.

Source: https://www.etvbharat.com/amp/en/bharat/bihar-encounter-case-police-requests-bhojpur-dm-to-appoint-magistrate-for-probe-enn26061906864

ETV Bharat / bharat

Bihar Encounter Case: Police Requests Bhojpur DM To Appoint Magistrate For Probe

Bihar Police have sought a magisterial enquiry into the encounter killing of mentally distressed youth Bharat Bhushan Tiwari, amid allegations of police misconduct and protests.
By Dev Raj
Published : June 19, 2026 at 8:40 PM IST

Patna: The Bihar Police wrote to the Bhojpur district magistrate on Friday to appoint a magistrate to conduct an enquiry into the encounter and subsequent death of a "mentally distressed" youth, Bharat Bhushan Tiwari, on Wednesday (June 17).

Abiding by the standard operating procedure (SOP) in encounter cases, we have written to the district magistrate to appoint an executive magistrate for independent enquiry in Bharat's case. It will be conducted along the 10 to 15 points fixed by the National Human Rights Commission (NHRC) in such incidents," Bhojpur Superintendent of Police (SP) Raj (goes by one name) told ETV Bharat.

Raj further said that the enquiry will also encompass ballistics and arms examination, as well as forensic tests, and the magisterial enquiry report would be submitted to the NHRC for further action.

The SOP in police encounters is governed by the guidelines laid down by the Supreme Court in the PUCL vs State of Maharashtra case (2014) and NHRC directives. It includes a mandatory FIR, preservation of evidence, independent investigation by an outside agency, magisterial inquiry, reporting to NHRC, forensic and ballistic tests, videography of the postmortem, and immediate suspension and prosecution of the policemen involved if it is proved that they committed an offence by using their firearms.

The Bhojpur SP clarified that the police personnel, including Shahpur station house officer (SHO) Rajesh Malakar, were "suspended not for the encounter but for the incident that had happened on Tuesday (June 16, a day before the encounter), in which Bharat had brandished a pistol and pointed it at them when they had visited his house to probe a social media post."

Raj added that Bharat was cremated by his family on the banks of the Ganga on Thursday, and the law and order situation in and around his native village, Bilauti, was under control.

However, amid the post-death rituals being performed for Bharat, his family was grieving his loss.

"The police have murdered my son. It was not an encounter. We watched him being shot after he surrendered to the police. We were not allowed to go near him. The villagers were also shooed away," Bharat's mother Asha Devi said. "The SHO knew that my son was mentally disturbed, yet he killed him despite being unarmed. I just want

justice and capital punishment for the people involved in this."

Bharat, a mentally distressed youth, used to raise issues related to the deprived sections of society, including flood protection and relief, as he wanted to change the indifferent administrative system, according to his family and locals.

Fed up with the lethargy of the government in providing relief to the people of neighbouring Jawaniya village displaced by floods and with no action despite running from pillar to post, he had posed with a pistol and posted its video on Facebook," they claimed.

"There is a small explosive message and a challenge to the chief minister of Bihar and the entire system of the state, especially the administration of Ara (Bhojpur) district. If the ditch provided to rehabilitate the helpless people of Jawaniya village is not properly filled with mud in a day or two… they, any person of the system, who comes here will be encountered, and a new revolutionary war in the country will be launched," the Facebook post said.

Someone complained about the post to the police, who visited his residence on June 16 to enquire about it. Bharat aimed a pistol at them and reiterated his demand. The police team went away, but a video of the incident became viral on social media and also found a place in the news.

The police returned the next day (June 17) and surrounded Bharat at his house. He started livestreaming it on Facebook and again threatened them by brandishing his firearm and managed to reach an open place in his village.

He aimed a pistol at the police officials and demanded that his demands, especially proper rehabilitation of flood victims at the nearby Jawaniya village and flood protection works for the area, be met.

Bharat threw away the firearm before the police and surrendered to them when they assured him that his demands would be taken to the concerned higher authorities and fulfilled. But at the same time, he expressed concern about his personal safety.

Bharat's family alleged that police shot him in cold blood after he surrendered. "He was hit by four bullets and was taken away to the district hospital and then to the Patna Medical College and Hospital (PMCH), where he succumbed to his injuries," they added.

Angered over his killing, the villagers and the relatives protested by blocking the national highway between Ara and Buxar on Thursday (June 18). They demanded a judicial probe or investigation by an independent agency, as well as action against the police personnel involved in the death of Bharat.

The deceased youth had no criminal record. He was into social service and had worked tirelessly during the COVID-19 pandemic lockdown to provide food to the poor. He continuously raised issues related to the people of his area.

Source: https://www.latestly.com/india/news/uttar-pradesh-nhrc-orders-probe-after-16-year-old-was-allegedly-kept-in-adult-jail-for-2-months-7481060.html

Uttar Pradesh: NHRC Orders Probe After 16-Year-Old Was Allegedly Kept in Adult Jail for 2 Months

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken independent, suo motu cognizance of reports that a 16-year-old minor boy was illegally detained as an adult inmate for more than two months at Kasna jail in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
By Meera | Published: Jun 19, 2026 06:30 PM IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken independent, suo motu cognizance of reports that a 16-year-old minor boy was illegally detained as an adult inmate for more than two months at Kasna jail in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. The rights body has demanded an immediate, detailed investigation into the matter from top state police and prison officials.

According to a media report dated June 16, 2026, the minor, a resident of Shahjahanpur district, was arrested on April 14, 2026. The youth reportedly received a phone call telling him to pick up a parcel in his name, but was taken into custody by police upon arrival at the location. Uttar Pradesh: CBI Court Sentences Man to 10 Years Imprisonment in 2015 Homicide Case of Pratapgarh Inspector Anil Kumar.

The police filed a First Information Report (FIR) against the boy under several severe sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). The report further alleges that police personnel physically assaulted the minor and forced him to sign blank documents.

Following his arrest, the teenager spent over two months housed alongside adult inmates at Kasna jail. It took an ossification test—a medical procedure used to estimate physical age—to officially confirm his status as a minor, after which it took an additional six days to transfer him to a local juvenile observation home. Despite later being granted bail by a court, the minor remains confined to the juvenile home. His family, reported to be living in extreme poverty, has been unable to arrange the financial surety bond required to secure his physical release. Uttar Pradesh: 36 Prisoners Test Positive for HIV in Lucknow District Jail, Total Cases Reach 47.

The initial arrest reportedly stemmed from a police crackdown following local protests by labourers who were demanding higher pay and improved working conditions in the district. Observing that the allegations indicate a severe violation of human rights, the NHRC issued formal notices to the Uttar Pradesh Director General of Police (DGP) and the Director General of Prisons Administration and Reform Services. Both departments are required to submit a comprehensive report on the incident within two weeks.

Additionally, the NHRC has directed its own Director General of Investigation to dispatch a specialized team to conduct an on-the-spot inquiry and present a separate report within one week.

Source: https://www.freepressjournal.in/india/citizens-lost-over-52976-crore-to-cyber-frauds-in-6-years-mha-data-reveals

Citizens Lost Over Rs52,976 Crore To Cyber Frauds In 6 Years; MHA Data Reveals

Indians lost more than Rs 52,976 crore to cyber-enabled frauds over the past six years, according to data presented during an NHRC discussion. Officials said digital arrest scams accounted for nearly 8% of the losses, while experts called for stronger regulation of communication platforms and enhanced measures to combat cybercrime.
Somendra SharmaUpdated: Friday, June 19, 2026, 10:35 PM IST

New Delhi, June 19: The National Human Rights Commission (NHRC), India, recently organised a discussion on 'Safeguarding Human Rights Against Digital Arrest Scams'.

Chairperson, NHRC, Justice V. Ramasubramanian emphasised the need for a collective response to tackle the menace and noted that Indians have lost about Rs 52,976 crore to cyber-enabled frauds during the past six years, with nearly eight per cent of the losses attributed to digital arrest scams.

The data has been compiled by the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) based on the National Cyber Crime Reporting Portal. He observed that in many reported cases, scamsters coerced their victims into transferring money by exploiting the fear of law enforcement agencies among people.

Senior functionaries representing different key departments of the Government of India, including the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Ministry of Telecommunications, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Reserve Bank of India (RBI), Central Bureau of Investigation (CBI), National Payments Corporation of India (NPCI), eminent legal and domain experts, and representatives of telecom operators and banking and fintech associations, participated in the discussion.

Elderly among worst affected

NHRC Secretary General Bharat Lal pointed out that cybercrimes mostly affect elderly persons, including retired government officials, professionals, industrialists and bankers, causing not only financial losses but also compromising their dignity, self-respect and psychological well-being.

Referring to information placed before the Supreme Court in a related matter, he said that more than 3,000 such frauds targeting elderly persons were reported last year.

CBI outlines enforcement measures

Astha Modi, Superintendent of Police, CBI, stated that large-scale digital arrest scams originate from cyber scam compounds in Southeast Asia and are sustained by mule accounts, telecom infrastructure, social media intermediaries and human trafficking.

She outlined the CBI's action against mule account networks, telecom infrastructure, social media intermediaries

and human trafficking networks, and referred to an AI-based chatbot for verification of CBI notices and summons.

TRAI seeks OTT regulation

During the meeting, TRAI flagged the urgent need to bring OTT communication platforms such as WhatsApp, Signal and Telegram, used for voice calls, messages and video calls, under an appropriate regulatory mechanism, noting that most digital arrest frauds have shifted to OTT channels.

Officials also suggested measures such as alerts or interruptions during unusually long calls to help prevent digital arrest scams.

Source: https://m.sakshipost.com/amp/news/andhrapradesh/ysrcp-mps-seek-nhrc-intervention-sai-krishna-kranthi-kumar-cases-480463

YSRCP MPs seek NHRC intervention in Sai Krishna, Kranthi Kumar cases
19 Jun, 2026 17:09 IST

YSRCP MPs Maddila Gurumoorthy and Gumma Thanuja Rani met the Chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC) and submitted a detailed representation seeking urgent intervention into the custodial death of Gade Sai Krishna and the suicide of P. Kranthi Kumar, alleging serious human rights violations, police excesses and abuse of authority in both cases.

The MPs urged the Commission to take immediate cognizance of the suspicious death of Sai Krishna, who was allegedly taken into police custody before his death. The representation highlighted allegations by family members regarding custodial torture, physical abuse, denial of information about his whereabouts and violations of constitutional safeguards. It sought an independent, impartial and time-bound inquiry into the circumstances leading to his detention, custody and death.

The delegation also brought to the notice of the NHRC the case of Kranthi Kumar, who allegedly died by suicide after prolonged police harassment. The representation referred to a self-recorded video purportedly made by Kranthi Kumar before his death, in which he allegedly accused Krishnalanka Circle Inspector Nagaraju of continuous harassment and mental torture. The MPs requested preservation and forensic examination of all digital evidence, including the viral video, mobile phone records and other electronic material connected to the case.

The MPs informed the Commission that both incidents involve allegations against the same police officer and urged the NHRC to examine whether the cases reveal a broader pattern of misconduct, abuse of authority, custodial excesses, intimidation and human rights violations. They requested the Commission to call for all relevant records, examine complaints and disciplinary history, and consider recommending an inquiry by an independent agency or a Special Investigation Team to ensure fairness, transparency and public confidence.

Maddila Gurumoorthy and Gumma Thanuja Rani said the deaths of Sai Krishna and Kranthi Kumar have raised serious concerns about police accountability, abuse of power and the protection of fundamental rights in Andhra Pradesh. They urged the NHRC to intervene urgently, conduct an independent inquiry, fix responsibility on those found guilty and ensure justice for the bereaved families while upholding constitutional values, human dignity and the rule of law.

Source: https://www.oneindia.com/india/nhrc-notice-jammu-demolition-alleged-gujjar-bakkarwal-homes-011-8123911.html#google_vignette

NHRC notice to Jammu officials after complaint over demolition of Gujjar Bakkarwal homes

The National Human Rights Commission has issued notices to the District Magistrate and Superintendent of Police, Jammu, following a complaint alleging the forced demolition of about 25 homes of the nomadic Gujjar Bakkarwal community in Village Dwara. The NHRC has sought an action taken report within two weeks, citing alleged displacement and Forest Rights Act concerns.
By Krishna Kripa Updated: Saturday, June 20, 2026, 0:12 [IST]

The National Human Rights Commission has sent notices to the District Magistrate and Superintendent of Police of Jammu. The move followed a complaint about an alleged forced demolition of about 25 homes. The houses belonged to the nomadic Gujjar Bakkarwal community. The case papers said the demolition occurred during peak summer heat in a Jammu village.

The NHRC has asked the two officials to file an action taken report within two weeks. The direction appeared in the case proceedings. The proceedings were dated June 17. The papers related to a complaint filed by a group in Delhi. The record listed "Advocate Sunil Kumar and others based in Delhi.

NHRC notice over Jammu demolition complaint

The complaint alleged the J&K Administration acted with the police force during the demolition. The location was listed as Village Dwara, Hamlet Bandi, Sidra. It also named Tehsil Jammu Khas, District Jammu, J&K. The complainants said around 25 houses were razed. The homes were linked to the Gujjar Bakkarwal community.

The complainants said the drive displaced families during 45 degree Celsius heat. The complaint claimed elderly parents, children, and infants were affected. The papers alleged the families were not allowed to remove belongings. The complaint described the result as sudden displacement. It said people were left without shelter during intense summer conditions.

NHRC notice cites Forest Rights Act and natural justice

The complaint argued the action breached the Forest Rights Act, 2006. It said the law applied in Jammu & Kashmir from October 2020. The complainants also referred to historical rights for the community. They said former rulers had granted such rights. The papers alleged these claims were ignored during the demolition.

The complainants further alleged the demolition was arbitrary and biased. The complaint said it amounted to a denial of natural justice. It also claimed victims were left homeless and destitute. The case record included the commission’s direction to seek official responses. It set a two-week timeline for the report.

The proceedings recorded the next step for the complaint. \"Let a copy of complaint be transmitted to the Superintendent of Police and the District Magistrate, Jammu, J&K, calling for an action taken report within two weeks, as per the proceedings.\" The NHRC notice remains linked to the allegations described in the June 17 case

papers.

With inputs from PTI

Source: https://www.socialnews.xyz/2026/06/19/minor-kept-in-up-jail-as-adult-for-over-two-months-nhrc-orders-probe/

Home » Law » Minor kept in UP jail as adult for over two months: NHRC orders probe

Minor kept in UP jail as adult for over two months: NHRC orders probe
Posted By: Gopi June 19, 2026

New Delhi, June 19 (SocialNews.XYZ) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report alleging that a 16-year-old boy was illegally confined as an adult inmate in Kasna jail in Uttar Pradesh's Gautam Budh Nagar district for more than two months before being shifted to a juvenile home.

Observing that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violation, the apex human rights body has issued notices to the Uttar Pradesh Director General of Prisons Administration and Reform Services and the Director General of Police (DGP), seeking a detailed report within two weeks.

The NHRC has also directed its Director General (Investigation) to depute a team of officers to conduct a spot enquiry and submit a report within a week.

According to the media report, the victim continues to remain in a juvenile home despite having been granted bail by a court, as his family has been unable to arrange the required surety bond due to financial constraints.

"The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violation of the victim," the NHRC said in a statement.

According to the media report carried on June 16, the boy, a resident of Shahjahanpur district, was arrested and lodged in Kasna jail as an adult inmate despite being a minor.

Reportedly, he was arrested following protests by labourers in the district demanding a pay hike and improved working conditions.

The report stated that the boy received a phone call on April 14, 2026, regarding a parcel in his name. However, when he arrived at the designated location, police personnel present there allegedly arrested him.

An FIR was subsequently registered against him under various serious provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). The police allegedly assaulted the boy and forced him to sign certain documents, according to the report.

The NHRC noted that even after an ossification test confirmed that he was a minor, it took six more days for authorities to transfer him from Kasna jail to a juvenile home.

Source: IANS

Siasat Daily, Online News, 20/06/2026

Source: https://www.siasat.com/hyderabad-advocate-moves-nhrc-over-2000-indian-sailors-in-gulf-3492527/

Hyd advocate moves NHRC over stranded Indian sailors in Gulf

Plea seeks government intervention to safeguard Indian crew members in Gulf waters.
Sakina Fatima Published: 19th June 2026 6:43 pm IST| Updated: 19th June 2026 6:49 pm IST

Hyderabad: The National Human Rights Commission (NHRC) has forwarded a complaint filed by Hyderabad-based advocate and human rights defender Yennam Balachander Reddy regarding nearly 2,000 Indian seafarers reportedly stranded in the Persian Gulf region to the Ministry of External Affairs (MEA) for appropriate action.

In an order dated on Friday, June 19, the Commission directed the concerned authority to examine the matter and take appropriate action within eight weeks. It also instructed the authority to associate the complainant and affected victims in the process and inform them of the action taken.

The complaint raised concerns over the safety and welfare of Indian sailors serving aboard merchant vessels operating in the Persian Gulf amid ongoing regional tensions and maritime security challenges.

According to the petition, approximately 2,000 Indian seafarers continue to work in sensitive waters of the Gulf region, where geopolitical uncertainty has heightened concerns about the safety of maritime personnel.

The complaint called for coordinated government measures to safeguard Indian citizens working in vulnerable international locations and highlighted the need for effective emergency-response mechanisms during periods of regional instability.

It also noted the important role played by seafarers in global trade and maritime commerce, while drawing attention to the risks faced by maritime workers during times of conflict and uncertainty.

The NHRC’s intervention brings the matter before the competent authorities for consideration and necessary action.

India is among the world’s largest providers of maritime manpower, with thousands of Indian seafarers serving on vessels across international waters. The issue has drawn attention to the challenges faced by maritime workers operating in conflict-prone regions and the need to ensure their safety and welfare.

The Commission has directed the concerned authority to respond within the stipulated timeframe and keep the complainant informed of the action taken.

Source: https://newsonair.gov.in/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-alleged-illegal-confinement-of-minor-boy-at-kasna-jail-in-uttar-pradesh/

NHRC takes suo motu cognizance of alleged illegal confinement of minor boy at Kasna jail in Uttar Pradesh
News On AIR | June 19, 2026 6:11 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report over an alleged illegal confinement of a minor boy as an adult inmate at Kasna jail in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. The media report alleged that the 16-year-old boy was kept in jail for more than two months before being shifted to a juvenile home.

The Commission issued notices to the Director General of Prisons Administration and Reform Services and the Director General of Police of Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It has also directed NHRC Director General (Investigation) to deputise a team of officers to conduct a spot inquiry and submit a report within a week.

The Morning Voice, Online News, 20/06/2026

Source: https://tmv.in/article/ysrcp-mps-move-nhrc-over-alleged-custodial-abuses-in-saikiran-and-krantikumar-cases-date=2026-06-20

YSRCP MPs Move NHRC Over Alleged Custodial Abuses In Sai kiran And Kranti kumar Cases
Gaddamidi Naveen June 20, 2026

YSR Congress Party MPs have urged the National Human Rights Commission (NHRC) to intervene urgently in two separate cases from Vijayawada involving the suspicious death of Gade Sai kiran and the alleged suicide of P. Kranti kumar, calling for an independent and time-bound probe into serious human rights violation allegations.

YSRCP MPs Maddila Gurumoorthy and Gumma Tanujarani submitted a detailed representation to NHRC Chairperson Justice Ram Subrahmanyam, seeking immediate attention to what they described as disturbing claims of custodial abuse and police misconduct.

In the case of Saikiran, the MPs alleged that there are credible accusations of custodial violence, abuse of power, and procedural lapses following his detention. The family has reportedly raised concerns that they were not informed about his whereabouts in a timely manner and that injuries and circumstances surrounding his death remain unexplained. They urged the commission to ensure a neutral, independent and time-bound investigation into the incident.

On the death of Krantikumar, the MPs pointed to allegations that sustained police harassment and mental pressure may have contributed to his suicide. They referred to a video said to have been recorded before his death, in which he allegedly accused Krishna Lanka Circle Inspector Nagaraju of repeated harassment and mental torture.

They also urged the NHRC to secure and examine all digital evidence , including mobile phone data and the viral video, and subject them to forensic analysis without delay. Noting that allegations in both cases point towards the same police officer, the MPs said the pattern raises serious concerns that warrant deeper scrutiny.

The representative further requested that the NHRC consider recommending a Special Investigation Team (SIT) if required, to ensure an impartial and comprehensive inquiry into both incidents.

Times of India, Online News, 20/06/2026

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/vijayawada/ysrcp-mps-seek-nhrc-intervention-in-sai-krishna-kranthi-kumar-cases/articleshow/131864224.cms

YSRCP MPs seek NHRC intervention in Sai Krishna, Kranthi Kumar cases
Samdani MN Jun 19, 2026, 11.14 PM IST

Vijayawada: YSRCP MPs Maddila Gurumoorthy and Gumma Thanuja Rani met the National Human Rights Commission (NHRC) chairman justice V Ramasubramanian and sought urgent intervention into the custodial death of Gade Sai Krishna and the suicide of P Kranthi Kumar. They alleged serious human rights violations, police excesses, and abuse of authority in both cases.
The MPs urged the Commission to take immediate cognizance of the suspicious death of Sai Krishna, who was allegedly taken into police custody before his death. The representation highlighted allegations by family members regarding custodial torture, physical abuse, denial of information about his whereabouts and violations of constitutional safeguards. It sought an independent, impartial and time-bound inquiry into the circumstances leading to his detention, custody and death.

The delegation also brought to the notice of the NHRC the case of Kranthi Kumar, who allegedly died by suicide after prolonged police harassment. The representation referred to a self-recorded video purportedly made by Kranthi Kumar before his death, in which he allegedly accused Krishnalanka circle inspector Nagaraju of continuous harassment and mental torture. The MPs requested preservation and forensic examination of all digital evidence, including the viral video, mobile phone records and other electronic material connected to the case.

The MPs informed the commission that both incidents involve allegations against the same police officer and urged the NHRC to examine whether the cases reveal a broader pattern of misconduct, abuse of authority, custodial excesses, intimidation and human rights violations. They requested the commission to call for all relevant records, examine complaints and disciplinary history, and consider recommending an inquiry by an independent agency or a Special Investigation Team to ensure fairness, transparency and public confidence.

Source: https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/ysrcp-mps-seek-nhrc-probe-into-two-police-linked-deaths-in-andhra-pradesh/article71122713.ece

YSRCP MPs seek NHRC probe into two police-linked deaths in Andhra Pradesh

Gurumoorthy, Thanuja Rani flag custodial death, suicide allegedly linked to same officer
Published - June 19, 2026 08:19 pm IST - VIJAYAWADA
The Hindu Bureau

YSR Congress Party MPs Maddila Gurumoorthy and Gumma Thanuja Rani on Friday approached the National Human Rights Commission (NHRC), seeking its intervention in two recent deaths in Andhra Pradesh that have triggered allegations of police misconduct and human rights violations.

The MPs met the Commission's Chairperson and submitted a memorandum seeking a comprehensive inquiry into the death of Gade Sai Krishna and the alleged suicide of P. Kranthi Kumar. They said both incidents had raised serious concerns about police conduct and accountability.

In their representation, the MPs sought an independent investigation into the circumstances surrounding Sai Krishna's death, alleging that he had been taken into police custody before the incident. Referring to concerns raised by his family members, they said questions remained over his treatment and whereabouts before his death. They urged the Commission to examine whether legal and constitutional safeguards were adhered to during the period of detention.

The delegation also highlighted the case of Kranthi Kumar, who allegedly died by suicide after facing sustained police pressure. Citing a video purportedly recorded by him before his death, they said he had named a police official and accused him of harassment. The MPs requested the NHRC to ensure the preservation and forensic examination of all relevant electronic evidence, including video recordings, mobile phone data and communication records.

Pointing out that allegations in both cases involve the same police officer, the MPs urged the Commission to examine whether the incidents reflected a pattern of abuse of authority. They called for a transparent inquiry, scrutiny of official records and consideration of an investigation by an independent agency.

The MPs said the two cases had generated widespread concern over civil liberties and police accountability. They urged the NHRC to take prompt action to ensure justice for the affected families and uphold the rule of law.

Dynamite News, Online News, 20/06/2026

Source: https://hindi.dynamitenews.com/crime/serious-allegation-against-police-in-noida-labor-protest-minor-sent-to-jail-by-falsely-recording-him-as-an-adult/amp

नोएडा श्रमिक आंदोलन में पुलिस ने कर दिया ऐसा कांड, गले में फंस गई हड्डी, NHRC ने DGP और DG जेल से मांगा जवाब

नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने एक 16 साल के नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दस्तावेजों में उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा दर्ज कर दी। मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यूपी डीजीपी और डीजी जेल से जवाब मांगा है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 20 June 2026, 7:49 AM IST

Noida Desk: नोएडा में जब मजदूरों का हिंसक आंदोलन हुआ था तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़े-बड़े एक्शन लिए थे, लेकिन इन एक्शन के बीच एक ऐसा कांड कर दिया। जिसकी वजह से गले में हड्डी फंस गई है। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले में एक्शन लिया है। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और डीजी जेल से पूरी रिपोर्ट मांगी है, मामला बहुत गंभीर है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, श्रमिक आंदोलन के दौरान पुलिस ने 16 साल के एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार का जेल भेज दिया। बड़ी बात यह है कि जब किशोर को जेल भेजा गया तो रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा लिख दी। मामला 14 अप्रैल का है। फेस-2 थाना पुलिस ने नाबालिग लड़के को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। वैसे लड़के की असली उम्र 16 साल है।

कैसे हुआ खुलासा?
इस मामले को खुलासा तब हुआ, जब वह पेशी के दौरान नाबालिग लड़का गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में आया। तभी एडवोकेट माणिक गुप्ता की नजर उस लड़के पर पड़ी। माणिक गुप्ता को लड़के की उम्र बहुत ज्यादा कम लग रही थी और हाथ में हथकड़ी थी। जब हथकड़ी ने उस नाबालिग लड़के से बात की तो पता चला कि उसकी उम्र को केवल अभी 16 वर्ष है।

एनएचआरसी ने मांगा जवाब
इस पर एडवोकेट माणिक गुप्ता ने नाबालिग लड़के का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज को इकट्ठा किया। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर 8 जून को उस लड़के को बाल सुधार भेजने के आदेश दिए गए। हालांकि, अब लड़के की जमानत हो गई है और उसको रिहा कर दिया गया है। यह मामला अब एनएचआरसी के पास पहुंच गया। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी है।

Hindustan Samachar, Online News, 20/06/2026

Source: https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2026/6/19/NHRC-NOTICE-UP-DGP-Ghaziabad.php

एनएचआरसी का नाबालिग को जेल में रखने को लेकर उप्र के डीजीपी व अन्य को नोटिस

19 Jun 2026 18:28:53

नई दिल्ली, 19 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के कासना जेल में एक नाबालिग को वयस्क कैदी की तरह हिरासत में रखने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन, सुधार सेवा महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

मीडिया की रिपोर्ट में अप्रैल महीने में गौतमबुद्ध नगर में मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तारी के बाद किशोर को कासना जेल भेज दिया गया। बाद में हुए मेडिकल टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह नाबालिग है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी उसे किशोर सुधारगृह में स्थानांतरित करने में प्रशासन को 6 दिन का समय लग गया।

पीड़ित युवक को जमानत मिल चुकी है लेकिन वह आज भी सुधारगृह में ही बंद है। उसका परिवार बेहद गरीब है और अदालत द्वारा तय की गई जमानत राशि का इंतजाम करने में असमर्थ है। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और डरा-धमकाकर जबरन कुछ खाली दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए।

एनएचआरसी अब इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रहा है। आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को भी निर्देश दिया है कि वे अधिकारियों की एक टीम को घटनास्थल पर जांच करने के लिए भेजें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-up-dgp-ghaziabadphp/cid18859437.htm

एनएचआरसी का नाबालिग को जेल में रखने को लेकर उप्र के डीजीपी व अन्य को नोटिस
By VocalTV Desk | Jun 19, 2026, 18:28 IST

नई दिल्ली, 19 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के कासना जेल में एक नाबालिग को वयस्क कैदी की तरह हिरासत में रखने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन, सुधार सेवा महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

मीडिया की रिपोर्ट में अप्रैल महीने में गौतमबुद्ध नगर में मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तारी के बाद किशोर को कासना जेल भेज दिया गया। बाद में हुए मेडिकल टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह नाबालिग है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी उसे किशोर सुधारगृह में स्थानांतरित करने में प्रशासन को 6 दिन का समय लग गया।

पीड़ित युवक को जमानत मिल चुकी है लेकिन वह आज भी सुधारगृह में ही बंद है। उसका परिवार बेहद गरीब है और अदालत द्वारा तय की गई जमानत राशि का इंतजाम करने में असमर्थ है। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और डरा-धमकाकर जबरन कुछ खाली दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए।

एनएचआरसी अब इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रहा है। आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को भी निर्देश दिया है कि वे अधिकारियों की एक टीम को घटनास्थल पर जांच करने के लिए भेजें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Dainik Bhaskar, Online News, 20/06/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/kasna-jail-mein-nabalig-ko-vayask-kaidi-ki-tarah-rakhne-ka-mamla-nhrc-ne-liya-svatah-sangyan-1316038

कासना जेल में नाबालिग को वयस्क कैदी की तरह रखने का मामला, एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान
19 June 2026 5:42 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गौतमबुद्धनगर स्थित कासना जेल में एक नाबालिग बालक को वयस्क कैदी के रूप में दो महीने से अधिक समय तक अवैध रूप से रखने की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस एवं जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ग्रेटर नोएडा, 19 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गौतमबुद्धनगर स्थित कासना जेल में एक नाबालिग बालक को वयस्क कैदी के रूप में दो महीने से अधिक समय तक अवैध रूप से रखने की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस एवं जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक, संबंधित बालक को जिले में मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे नाबालिग होने के बावजूद कासना जेल में वयस्क कैदियों के बीच रखा गया। बताया जा रहा है कि करीब दो महीने से अधिक समय तक जेल में रखने के बाद उसे किशोर न्याय प्रणाली के तहत एक बाल सुधार गृह (जुवेनाइल होम) में स्थानांतरित किया गया। एनएचआरसी ने इस मामले को बच्चों के अधिकारों और मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय माना है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के महानिदेशक तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी कहा कि यदि मीडिया रिपोर्टों में वर्णित तथ्य सही पाए जाते हैं तो यह न केवल किशोर न्याय कानूनों के उल्लंघन का मामला होगा, बल्कि संबंधित बालक के मौलिक और मानवाधिकारों के हनन का भी गंभीर उदाहरण माना जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिकारियों की एक टीम गठित कर घटनास्थल का निरीक्षण कराएं और एक सप्ताह के भीतर स्वतंत्र जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपें। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत द्वारा बालक को जमानत दिए जाने के बावजूद वह अभी तक बाल गृह में ही रह रहा है। इसका कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बताई जा रही है। परिवार जमानत के लिए आवश्यक जमानती और औपचारिकताएं पूरी करने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते बालक को रिहाई नहीं मिल सकी है।

Amar Ujala, Online News, 20/06/2026

Source: https://www.amarujala.com/amp/delhi-ncr/noida/gsfdg-grnoida-news-c-23-1-lko1064-97909-2026-06-19

Noida News: नाबालिग को जेल में रखने पर एनएचआरसी सख्त, डीजीपी व डीजी जेल को नोटिस
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 08:57 PM IST

- श्रमिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार 16 वर्षीय किशोर को बालिग बताकर भेजा गया था लुक्सर जेल

- एनएचआरसी ने दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट, महानिदेशक को विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। श्रमिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 16 वर्षीय किशोर को बालिग दर्शाकर लुक्सर जिला जेल भेजने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और महानिदेशक कारागार (डीजी जेल) को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।
एनएचआरसी ने मामले की स्वतंत्र जांच के लिए अपने महानिदेशक को विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश भी दिया है। आयोग ने एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नाबालिग को वयस्क कैदियों के बीच रखने की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। जानकारी के अनुसार फेज-2 थाना पुलिस ने 14 अप्रैल 2026 को श्रमिक आंदोलन से जुड़े मामले में एक किशोर को गिरफ्तार किया था। पुलिस दस्तावेजों में उसे बालिग दर्शाते हुए लुक्सर जेल भेज दिया था। बाद में न्यायालय परिसर में हथकड़ी लगे किशोर को देखकर एक अधिवक्ता को उसकी उम्र पर संदेह हुआ। पूछताछ में किशोर ने स्वयं को नाबालिग बताया।

इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनसे उसकी उम्र 16 वर्ष साबित हुई। दस्तावेजों की जांच के बाद अदालत ने 8 जून को उसे वयस्क जेल से हटाकर बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। भंगेल निवासी किशोर एक परचून की दुकान पर काम करता है। आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद बृहस्पतिवार को किशोर को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया।

Source: https://jaihindjanab.com/minor-spent-two-months-in-an-adult-jail-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-and-seeks-a-response-from-the-up-police-and-jail-administration/

दो महीने वयस्क जेल में बंद रहा नाबालिग, अब NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान, यूपी पुलिस-जेल प्रशासन से मांगा जवाब
June 20, 2026Avinash Kumar

कासना जेल में 16 वर्षीय किशोर को बालिग मानकर रखा गया, अदालत के आदेश पर बाल सुधार गृह भेजा गया, छह दिन बाद जमानत पर रिहाई

गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों के वेतन वृद्धि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए एक 16 वर्षीय किशोर को पुलिस ने बालिग मानकर दो महीने से अधिक समय तक कासना की लुक्सर जेल में वयस्क कैदियों के बीच रखा। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) तथा जेल महानिदेशक (DG Prisons) को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

क्या है मामला

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 14 अप्रैल को थाना फेस-2 पुलिस ने नोएडा के भंगेल इलाके में मजदूरों के वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा के आरोप में किशोर को हिरासत में लिया था। किशोर के वकील के मुताबिक गिरफ्तारी और रिमांड दस्तावेजों में उसकी उम्र 25 वर्ष दर्ज कर दी गई, जबकि उसके आधार कार्ड में उम्र महज 16 वर्ष है। इसी गलत प्रविष्टि के आधार पर उसे वयस्क आरोपी मानकर कासना स्थित लुक्सर जेल भेज दिया गया, जहां वह करीब दो महीने तक बालिग कैदियों के साथ बंद रहा।

परिवार का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद न तो उन्हें सूचित किया गया और न ही किशोर को वकील से मिलने दिया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के लगभग एक महीने बाद ही उसे कानूनी प्रतिनिधित्व मिल सका। परिवार और वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि हिरासत में किशोर के साथ मारपीट की गई और उसे अदालत में हथकड़ी-जंजीरों में बांधकर पेश किया गया, जो किशोर न्याय अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है।

अदालत में वकील की नजर पड़ी, खुला राज

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता माणिक गुप्ता की नजर हथकड़ी में पेश किशोर पर पड़ी और बातचीत में उसने खुद को नाबालिग बताया। इसके बाद वकील ने उसका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जुटाकर अदालत में पेश किए, जिनकी जांच में उसकी उम्र 16 वर्ष होने की पुष्टि हुई। 29 मई को गौतमबुद्ध नगर की एक सत्र अदालत ने किशोर को जमानत दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किशोर का नाम FIR में दर्ज नहीं था और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सीसीटीवी, वीडियो या फोटोग्राफिक सबूत मौजूद नहीं था जिससे घटना में उसकी भूमिका साबित होती हो। गवाहों के बयान भी उसकी कोई स्पष्ट संलिप्तता नहीं दर्शाते थे।

जमानत के बावजूद हफ्तों जेल में रहना पड़ा

जमानत मंजूर होने के बावजूद किशोर तुरंत रिहा नहीं हो सका, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह जमानत के लिए जरूरी 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 45 हजार रुपये की राशि नहीं जुटा पा रहा था। इस बीच 6 जून को उसकी ओसिफिकेशन जांच (हड्डी परीक्षण से उम्र के आकलन की प्रक्रिया) की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष ही आंकी गई। यह पुष्टि होने के बावजूद उसे छह दिन और वयस्क जेल में ही रखा गया। अदालत ने 8 जून को आदेश जारी कर उसे वयस्क जेल से निकालकर बाल सुधार गृह (किशोर गृह) भेजने का निर्देश दिया, जिसके बाद 12 जून को उसे स्थानांतरित किया गया। बाद में अदालत ने जमानत राशि को 45 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर दिया। जमानत के बदले एक मोटरसाइकिल के दस्तावेज जमा कराने के बाद 18 जून को किशोर को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया। इस तरह वह कुल मिलाकर लगभग दो महीने वयस्क जेल और छह दिन किशोर गृह में बिताने के बाद आज़ाद हुआ। जांच में सामने आया कि किशोर भंगेल क्षेत्र का रहने वाला है और एक किराना दुकान पर काम करता था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के समय किशोर ने खुद को बालिग बताया था, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई हुई। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ इस सफाई पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि उम्र को लेकर थोड़ा भी संदेह होने पर दस्तावेजी सत्यापन अनिवार्य होता है, खासकर तब जब

मामला किशोर न्याय कानून से सीधे जुड़ा हो।

NHRC का स्वतः संज्ञान, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने इसे एक नाबालिग को दो महीने से अधिक समय तक अवैध रूप से वयस्क कैदी के तौर पर बंद रखने का बेहद गंभीर मामला बताया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और डीजी जेल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है, जबकि अपने महानिदेशक (इन्वेस्टिगेशन) को एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। आयोग की प्राथमिकता यह स्पष्ट करना है कि उम्र सत्यापन की प्रक्रिया में चूक आखिर किस स्तर पर हुई गिरफ्तारी के समय, रिमांड दस्तावेज तैयार करते समय या जेल में दाखिले के दौरान और इस गंभीर लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। मामला अब पुलिस और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, खासकर इस बात पर कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में वर्षों से लागू किशोर न्याय अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद आधार जैसे पहचान दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की गई। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि के विरुद्ध किसी भी बालक की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इसलिए इस रिपोर्ट में पीड़ित किशोर का नाम प्रकाशित नहीं किया गया है।

Rojana Spokesman, Online News, 20/06/2026

Source: https://spokesmanhindi.com/national/uttar-pradesh/190626/the-national-human-rights-commission-has-strongly-condemned-the-deaths.html

शीतला माता मंदिर में 8 लोगों की मौत पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क कड़ी निंदा
By : RATTUR
Published : Jun 19, 2026, 10:19 pm IST
Updated : Jun 19, 2026, 10:21 pm IST

बिहार DGP और नालंदा SP से मांगी रिपोर्ट
बिहार: 31 मार्च को नालंदा के मघरा शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कमीशन ने इस घटना के संबंध में बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और नालंदा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के अंदर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है।

एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही से 8 लोगों की मौत

31 मार्च को मघरा शीतला माता मंदिर में खराब मैनेजमेंट और भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। इस संबंध में, दिल्ली के एक वकील, नालंदा निवासी ब्रजेश सिंह ने 2 अप्रैल को कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे 18 जून को विचार के लिए कमीशन के सामने रखा गया था।

इस गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी की ओर कमीशन का ध्यान दिलाते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने मंदिर की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही दिखाई है। घटना के समय, मंदिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था, क्योंकि पुलिस और प्रशासनिक संसाधन एक ही समय में राष्ट्रपति के नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चल रहे दौरे की सुरक्षा के लिए तैनात थे।

NHRC ने सख्त निर्देश किए जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना और लॉ डिपार्टमेंट के जॉइंट रजिस्ट्रार, इंद्रजीत कुमार के जरिए अधिकारियों को एक पत्र जारी किया। आयोग ने निर्देश दिया कि शिकायत की एक कॉपी नालंदा के पुलिस अधीक्षक और बिहार के DGP को भेजी जाए। दोनों वरिष्ठ अधिकारी 4 हफ्ते के अंदर मामले में अब तक हुई चूक और की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट दें। 4 हफ्ते बाद मामले को समीक्षा के लिए फिर से आयोग के सामने रखा जाए।

उच्च स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग

शिकायतकर्ता वकील ब्रजेश सिंह ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, लापरवाह और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जवाबदेही और सख्त कार्रवाई और पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवज़ा देने की मांग की है।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-human-rights-commission-issues-notice-over-minor-held-as-adult-in-kasna-jail-201781881254400.amp.html

नाबालिग को जेल में रखने पर यूपी जेल के महानिदेशक से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब
Jun 19, 2026 10:42 pm IST
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की कासना जेल में एक नाबालिग को दो माह से अधिक समय तक बालिग कैदी के तौर पर रखने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। नाबालिग की पुष्टि के बावजूद उसे बाल सुधार गृह भेजने में देरी हुई।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की कासना जेल में एक नाबालिग को दो माह से अधिक समय तक बालिग कैदी के तौर पर जेल में रखने जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेल प्रशासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग ने घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। पीड़ित के नाबालिग होने के पुष्टि होने के बाद भी बाल सुधार गृह भेजने में छह दिन का वक्त लग गया।

घटना का विवरण
आयोग ने उन खबरों पर संज्ञान लेकर यह आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक 16 साल के नाबालिग को गौतम बुद्ध नगर जिले के कासना जेल में बालिग कैदी के रूप में दो माह तक अवैध रूप से रखा गया और नाबालिग होने की पुष्टि होने के बाद उसे बाल सुधार गृह में स्थानांतरित करने में छह दिन और लग गए। लेकिन अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद वह किशोर गृह में ही है क्योंकि उसका गरीब परिवार जमानती (मुचलके) की व्यवस्था नहीं कर सका। नाबलिग को नोएडा पुलिस ने मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था॰

मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई
मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो इससे पीड़ित के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला उठता है। इसलिए आयोग ने उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवयाब देने एवं विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को भी निर्देश दिया है कि वे अधिकारियों की एक टीम को घटनास्थल पर जांच करने के लिए भेजें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सामान्य प्रश्न
✦
यह मामला किस जेल से संबंधित है?
यह मामला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की कासना जेल से संबंधित है।
✦
मानवाधिकार आयोग ने किसको नोटिस जारी किया है?

Source: https://www.amarujala.com/amp/city-and-states/national-human-rights-commission-observer-visits-newborn-jhajjar-news-c-200-1-bgh1002-124715-2026-06-20

नवजात को देखने पहुंचे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पर्यवेक्षक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2026 02:30 AM IST

बहादुरगढ़। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक बालकृष्ण गोयल पांच दिन पहले मिले नवजात शिशु की स्थिति का जायजा लेने ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी ली, जिस पर चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा अब स्वस्थ है और दूध पीने लगा है।

गोयल ने अस्पताल के रिकॉर्ड और पुलिस विवेचना फाइल की जांच की जिसमें कुछ त्रुटियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई हालांकि अस्पताल द्वारा की जा रही देखभाल की उन्होंने सराहना की। उन्होंने पुलिस द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी न होने और किशोर कल्याण अधिकारी की अनुपस्थिति पर भी आपत्ति जताई।

इसके साथ ही जिला बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया में लापरवाही और औपचारिकताओं को लेकर भी उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। बाद में उन्होंने जिला बाल संरक्षण यूनिट से बात कर नवजात को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर सरकारी शिशु गृह में स्थानांतरित करवाया।

Khas Khabar, Online News, 20/06/2026

Source: https://www.khaskhabar.com/local/uttar-pradesh/greater-noida-news/news-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-minor-being-held-like-an-adult-prisoner-in-kasna-jail-news-hindi-1-822662-KKN.html

कासना जेल में नाबालिग को वयस्क कैदी की तरह रखने का मामला, एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान
khaskhabar.com: शुक्रवार, 19 जून 2026 5:32 PM

ग्रेटर नोएडा । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गौतमबुद्धनगर स्थित कासना जेल में एक नाबालिग बालक को वयस्क कैदी के रूप में दो महीने से अधिक समय तक अवैध रूप से रखने की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस एवं जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक, संबंधित बालक को जिले में मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे नाबालिग होने के बावजूद कासना जेल में वयस्क कैदियों के बीच रखा गया। बताया जा रहा है कि करीब दो महीने से अधिक समय तक जेल में रखने के बाद उसे किशोर न्याय प्रणाली के तहत एक बाल सुधार गृह (जुवेनाइल होम) में स्थानांतरित किया गया।

एनएचआरसी ने इस मामले को बच्चों के अधिकारों और मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय माना है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग के महानिदेशक तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने यह भी कहा कि यदि मीडिया रिपोर्टों में वर्णित तथ्य सही पाए जाते हैं तो यह न केवल किशोर न्याय कानूनों के उल्लंघन का मामला होगा, बल्कि संबंधित बालक के मौलिक और मानवाधिकारों के हनन का भी गंभीर उदाहरण माना जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिकारियों की एक टीम गठित कर घटनास्थल का निरीक्षण कराएं और एक सप्ताह के भीतर स्वतंत्र जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपें।
रिपोर्टों के अनुसार, अदालत द्वारा बालक को जमानत दिए जाने के बावजूद वह अभी तक बाल गृह में ही रह रहा है। इसका कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बताई जा रही है। परिवार जमानत के लिए आवश्यक जमानती और औपचारिकताएं पूरी करने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते बालक को रिहाई नहीं मिल सकी है।

--आईएएनएस

Source: https://insamachar.com/nhrc-has-taken-suo-motu-cognizance-of-the-case-where-a-minor-boy-was-illegally-detained-like-an-adult-prisoner-for-over-two-months-in-ups-kasna-jail/

NHRC ने यूपी के कासना जेल में एक नाबालिग लड़के को दो महीने से अधिक समय तक वयस्क कैदी की तरह अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया
Editor Posted on19 जून 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक 16 वर्षीय लड़के को गौतम बुद्ध नगर जिले के कासना जेल में वयस्क कैदी के रूप में दो महीने तक अवैध रूप से रखा गया। अस्थि परीक्षण से नाबालिग होने की पुष्टि होने के बाद उसे जिले के एक किशोर गृह में स्थानांतरित करने में छह दिन और लग गए। लेकिन अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद वह किशोर गृह में ही है, क्योंकि उसका गरीब परिवार जमानती (मुचलके) की व्यवस्था नहीं कर सका। खबरों के अनुसार, जिले में मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।

आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो इससे पीड़ित के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला उठता है। अतः आयोग ने उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को भी निर्देश दिया है कि वे अधिकारियों की एक टीम को घटनास्थल पर जांच करने के लिए भेजें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

16 जून 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लड़के को 14 अप्रैल 2026 को उसके नाम से एक पार्सल के संबंध में फोन आया। हालांकि, वहां पहुंचते ही मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। खबरों के अनुसार, पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

Now Noida, Online News, 20/06/2026

Source: https://nownoida.com/noida-news/details/7466/nhrc-notice-greater-noida-minor-jailed-adult-prison-two-months-case

नोएडा में किशोर को 2 महीने जेल में रखने का मामला तूल पर, NHRC ने लिया संज्ञान, यूपी DGP और DG जेल से मांगी रिपोर्ट

ग्रेटर नोएडा में 16 वर्षीय किशोर को दो महीने वयस्क जेल में रखने के मामले में NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने यूपी डीजीपी और डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी है। मामला पुलिस और जेल प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
Shiv Kumar 19 Jun, 2026

ग्रेटर नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए एक 16 वर्षीय किशोर को कथित रूप से दो महीने से अधिक समय तक वयस्क जेल में रखने का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। आयोग ने इस गंभीर प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे संभावित मानवाधिकार उल्लंघन माना है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी तथा डीजी जेल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही आयोग ने अपने स्तर पर भी जांच टीम गठित कर एक सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मामला 14 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरोप में फेज-2 थाना पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि पुलिस रिकॉर्ड में उसकी उम्र गलत तरीके से बालिग दर्ज कर दी गई, जिसके बाद उसे कासना स्थित लुक्सर जेल भेज दिया गया। वहां वह करीब दो महीने तक वयस्क बंदियों के साथ रहा। इस दौरान किसी भी स्तर पर उसकी सही उम्र की पुष्टि को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

पेशी के दौरान हुआ खुलासा, आधार कार्ड से सामने आई सच्चाई

पूरा मामला तब सामने आया जब एक पेशी के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता माणिक गुप्ता की नजर किशोर पर पड़ी। बातचीत में किशोर ने खुद को नाबालिग बताया, जिसके बाद अधिवक्ता ने उसके दस्तावेजों की जांच शुरू की। आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों से स्पष्ट हुआ कि उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। इसके बाद यह मामला अदालत के संज्ञान में लाया गया। दस्तावेजों की पुष्टि के बाद अदालत ने 8 जून को आदेश जारी करते हुए किशोर को वयस्क जेल से हटाकर बाल सुधार गृह भेजने का निर्देश दिया। बाद में जमानत प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे रिहा कर दिया गया।

आर्थिक तंगी बनी जमानत में बाधा

जांच में यह भी सामने आया कि किशोर भंगेल क्षेत्र का रहने वाला है और एक परचून की दुकान पर काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जमानत के लिए आवश्यक श्योरिटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से उसे लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ा। बाद में अदालत ने मानवीय आधार पर जमानत राशि 45 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर दी, जिसके बाद एक बाइक के दस्तावेज जमा कराए गए और जमानत प्रक्रिया पूरी हुई।

पुलिस और जेल प्रशासन सवालों के घेरे में

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के समय किशोर ने खुद को बालिग बताया था, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि उम्र सत्यापन की प्रक्रिया में चूक कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक नाबालिग को दो महीने तक वयस्क कैदियों के बीच क्यों रखा गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। NHRC की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस पूरे मामले में किस स्तर पर लापरवाही हुई। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन दोनों की भूमिका गंभीर जांच के दायरे में आ गई है, और मामला प्रशासनिक स्तर पर बड़ी बहस का विषय बन गया है।

Source: https://www.etvbharat.com/hi/state/maghra-shitala-temple-stampede-nhrc-notice-to-bihar-dgp-and-nalanda-sp-brs26061902303

ETV Bharat / state

बिहार DGP और नालंदा SP को नोटिस...शीतला मंदिर भगदड़ मामले में NHRC ने मांगी रिपोर्ट

मघड़ा मंदिर भगदड़ मामले में NHRC ने बिहार DGP और नालंदा SP से 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी, प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Bihar Team
Published : June 19, 2026 at 12:39 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा के मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर भगदड़ मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए बिहार के डीजीपी विनय कुमार और नालंदा के एसपी भारत सोनी को पत्र जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है. कानून प्रभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार इंद्रजीत कुमार ने यह पत्र भेजा है.

प्रशासनिक विफलता का आरोप: दिल्ली हाई कोर्ट के वकील ब्रजेश सिंह की शिकायत पर आयोग ने यह कार्रवाई की है. शिकायत के अनुसार, 31 मार्च 2026 को हुई यह घटना प्रशासनिक विफलता और खराब भीड़ प्रबंधन का नतीजा थी. घटना के समय जिले का पुलिस बल राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों और वीआईपी ड्यूटी में लगा था. इस कारण मंदिर में भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं थे.

आयोग की मांगें और निर्देश: आयोग ने घटना के कारणों की निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं. लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और पीड़ितों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की बात कही गई है. बिहार पुलिस मुख्यालय और नालंदा प्रशासन को अब 4 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई.

क्या था मामला?: नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा स्थित शीतला मंदिर में 31 मार्च की सुबह-सुबह अचानक भगदड़ मच गई थी. चैत महीने का आखिरी मंगलवार होने के कारण वहां 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी. मंदिर में पूजा के दौरान अचानक मची इस भगदड़ में कुल 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी. हालांकि प्रशासन ने 8 की पुष्टि की थी.

भगदड़ और अव्यवस्था का कारण: स्थानीय लोगों के अनुसार, भीड़ के बीच किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार को आवाज देने के लिए मचाए गए शोर से हंगामा हुआ और भगदड़ मच गई थी. मंदिर के पुजारी गुट्टू सिंह ने बताया था कि अत्यधिक भीड़ के कारण कई श्रद्धालुओं का ब्लड प्रेशर गिर गया था. मंदिर परिसर में जगह नहीं थी और एम्बुलेंस भी काफी देरी से पहुंची थी.

Source: https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/gautambudh-nagar/news/nhrc-takes-cognizance-minor-adult-jail-up-labour-protest-138233927.html

Hindi NewsLocalUttar pradeshGautambudh nagarNHRC Notice UP DGP, DG Jail | Minor In Adult Jail 2 Months, Labour Protest

नोएडा में किशोर को 2 महीने जेल में रखा:NHRC ने लिया संज्ञान, यूपी DGP और DG जेल से मांगी रिपोर्ट
नोएडा 15 घंटे पहले

ग्रेटर नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 16 साल के किशोर को दो महीने से अधिक समय तक जेल में रखने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन का गंभीर मामला माना है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और डीजी जेल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

इसके साथ ही आयोग ने अपने महानिदेशक को जांच टीम गठित कर एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बालिग दिखाकर भेज दिया गया था जेल

मामला 14 अप्रैल का है। श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरोप में फेज-2 थाना पुलिस ने एक किशोर को गिरफ्तार किया था। पुलिस रिकॉर्ड में उसकी उम्र बालिग दर्ज कर उसे कासना स्थित लुक्सर जेल भेज दिया गया। वहां वह करीब दो महीने तक वयस्क बंदियों के साथ रहा।

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पेशी के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता माणिक गुप्ता की नजर किशोर पर पड़ी। उन्होंने बताया कि किशोर को हथकड़ी में देखकर बातचीत की गई, जिसमें उसने खुद को नाबालिग बताया।

आधार कार्ड ने खोली पूरी कहानी

अधिवक्ता ने किशोर के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जुटाकर अदालत में प्रस्तुत किए। दस्तावेजों से उसकी उम्र 16 वर्ष साबित हुई। इसके बाद अदालत ने 8 जून को आदेश जारी कर किशोर को वयस्क जेल से हटाकर बाल सुधार गृह भेजने का निर्देश दिया।

गरीबी बनी जमानत में बाधा

जांच में सामने आया कि किशोर भंगेल क्षेत्र का रहने वाला है और एक परचून की दुकान पर काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह जमानत के लिए आवश्यक श्योरिटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था।

बाद में अदालत ने जमानत राशि 45 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर दी। एक बाइक के दस्तावेज जमानत के तौर पर जमा कराए गए, जिसके बाद गुरुवार को किशोर को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया।

अब जांच के घेरे में पुलिस और जेल प्रशासन

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के समय किशोर ने खुद को बालिग बताया था और उसी आधार पर कार्रवाई की गई। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि उम्र सत्यापन की प्रक्रिया में चूक कैसे हुई और एक नाबालिग को दो महीने तक वयस्क कैदियों के बीच क्यों रखा गया।

NHRC की जांच अब यह तय करेगी कि इस मामले में किस स्तर पर लापरवाही हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आयोग की कार्रवाई के बाद पुलिस

और जेल प्रशासन दोनों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है।

Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/noida/minor-sent-to-adult-jail-nhrc-takes-cognizance/articleshow/131864024.cms

hindi Newsstateuttar pradeshnoidaMinor Sent To Adult Jail Nhrc Takes Cognizance

Noida: नाबालिग को बालिग बताकर भेज दिया जेल, दो महीने बाद खुली सच्चाई; NHRC ने मांगी रिपोर्ट
Edited by: देवेश पांडेय|Lipi•19 Jun 2026, 11:20 pm IST

गौतमबुद्ध नगर में श्रमिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार 16 वर्षीय किशोर को पुलिस ने बालिग मानकर वयस्क जेल भेज दिया, जहां वह दो महीने से अधिक समय तक रहा।

मनीष सिंह, नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में श्रमिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए एक 16 वर्षीय किशोर को दो महीने से अधिक समय तक वयस्क जेल में रखने का मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को संभावित मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। आयोग ने डीजीपी और डीजी जेल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जबकि अपने महानिदेशक को एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला अब पुलिस और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर एक नाबालिग को बालिग मानकर वयस्क कैदियों के बीच दो महीने तक कैसे रखा गया और उम्र सत्यापन की प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।

श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई थी गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में हुए श्रमिक आंदोलन और उससे जुड़ी हिंसा के आरोप में थाना फेस-2 पुलिस ने एक किशोर को गिरफ्तार किया था। पुलिस रिकॉर्ड में उसकी उम्र बालिग दर्ज की गई और उसे कासना स्थित लुक्सर जेल भेज दिया गया।

इसके बाद किशोर लगभग दो महीने तक वयस्क कैदियों के साथ जेल में बंद रहा। इस दौरान उसकी वास्तविक उम्र की पुष्टि नहीं की गई, जिससे मामला और गंभीर हो गया।

अदालत में खुली नाबालिग होने की सच्चाई
मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक अदालत पेशी के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता माणिक गुप्ता की नजर हथकड़ी में मौजूद किशोर पर पड़ी। बातचीत के दौरान किशोर ने खुद को नाबालिग बताया।

इसके बाद अधिवक्ता ने उसके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जुटाकर अदालत में पेश किए। दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि किशोर की उम्र केवल 16 वर्ष है। यह तथ्य सामने आते ही अदालत ने 8 जून को आदेश जारी कर उसे वयस्क जेल से निकालकर बाल सुधार गृह भेजने का निर्देश दिया।

आर्थिक तंगी बनी जमानत में बाधा
जांच में पता चला कि किशोर भंगेल क्षेत्र का रहने वाला है और एक किराना दुकान पर काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जमानत के लिए जरूरी गारंटी और राशि जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।

बाद में अदालत ने जमानत राशि को 45 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर दिया। जमानत के बदले एक मोटरसाइकिल के दस्तावेज जमा कराने के बाद गुरुवार को किशोर को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया।

पुलिस ने दी सफाई
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के समय किशोर ने खुद को बालिग बताया था और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। हालांकि इस सफाई के बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस और अन्य एजेंसियों ने उम्र की पुष्टि के लिए उपलब्ध दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आरोपी की उम्र को लेकर संदेह की स्थिति में दस्तावेजों और अन्य प्रमाणों के आधार पर सत्यापन करना जरूरी होता है, विशेषकर तब जब मामला किशोर न्याय कानून से जुड़ा हो।

NHRC की जांच पर टिकी निगाहें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग यह पता लगाएगा कि उम्र सत्यापन की प्रक्रिया में चूक किस स्तर पर हुई और एक नाबालिग को वयस्क जेल में रखने के लिए कौन जिम्मेदार है।

Dainik Bhaskar, Online News, 20/06/2026

Source:
https://www.bhaskar.com/local/bihar/bhojpur/arrah/news/petition-in-nhrc-on-encounter-senior-advocate-saurabh-reached-the-village-dbp-138236936.html

Hindi NewsLocalBiharBhojpurArrahPetition In NHRC On Encounter, Senior Advocate Saurabh Reached The Village

एनकाउंटर में एनएचआरसी में याचिका, वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ पहुंचे गांव
आरा 3 घंटे पहले

भास्कर न्यूज | आरा

बिलौटी गांव में 17 जून को भरत भूषण तिवारी उर्फ भारत तिवारी के एनकाउंटर के सिलसिले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी बिलौटी पहुंचे। मृतक के पिता काशी नाथ तिवारी से मुलाकात कर परिवार को कानूनी लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान काशी नाथ तिवारी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवनभर पुलिस विभाग में रहकर कानून की सेवा की। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ही बिरादरी के लोग उनके बेकसूर और होनहार बेटे की जान ले लेंगे। उनका बेटा बाढ़ पीड़ितों के हक की आवाज उठा रहा था। उसने पुलिस के सामने आत्म-समर्पण कर दिया था। फिर भी उसे पांच गोलियां मारी गईं। परिवार टूट चुका है। न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। दोषियों को जेल भिजवाकर ही दम लेंगे। उधर परिवार से मिलने के बाद सौरभ तिवारी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में औपचारिक शिकायत याचिका दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर नहीं है। यह सत्ता और वर्दी के अहंकार में की गई हिरासत में हत्या है। मृतक ने फेसबुक लाइव के दौरान हथियार जमीन पर रखकर सरेंडर कर दिया था। इसके बाद भी उसे गिरफ्तार करने के बजाय पांच गोलियां क्यों मारी गईं। यह सुप्रीम कोर्ट के पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन और अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई कि जांच बिहार पुलिस से हटाई जाए। जांच सीबीआई या किसी उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक आयोग से कराई जाए। दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या की धाराओं में तुरंत केस दर्ज हो।डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए जाएं। इसमें फेसबुक लाइव वीडियो, घटना के वक्त मौजूद पुलिस अधिकारियों के मोबाइल टावर लॉग्स, पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी शामिल है।

Source: https://journomirror.com/case-of-jahangir-khans-public-humiliation-reaches-nhrc-impartial-probe-demanded/

NHRC पहुंचा जहांगीर खान के सार्वजनिक अपमान का मामला, निष्पक्ष जांच की मांग
June 19, 2026

पश्चिम बंगाल के चर्चित जहांगीर खान मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का दरवाज़ा खटखटाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए जहांगीर खान के साथ कथित हिरासत के दौरान सार्वजनिक अपमान और मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतंत्र जांच की मांग की है। शिकायत प्राप्त होने के बाद NHRC ने इसे डायरी नंबर 13814/IN/2026 के तहत दर्ज किया है।

हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह मामला राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी भी आरोपी को कानून लागू करने के नाम पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन यदि हिरासत के दौरान उसे सार्वजनिक रूप से इस तरह पेश किया जाता है जिससे उसकी गरिमा प्रभावित हो, तो यह संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।

सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि उनकी शिकायत किसी व्यक्ति का बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि इस सिद्धांत की रक्षा के लिए है कि "कानून का शासन किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अधिकार नहीं देता।

उन्होंने NHRC से मामले का स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने तथा यदि मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी ने कहा, आज मुद्दा केवल जहांगीर खान का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या भारत में हर आरोपी की मानवीय गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित रहेगी। मानवाधिकार किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या अलोकप्रियता पर निर्भर नहीं करते। लोकतंत्र में कानून के शासन और मानवीय गरिमा—दोनों की समान रूप से रक्षा होना आवश्यक है।

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
19.06.2026	NTV Telugu	16:00	YSRCP Files Complaint To NHRC Over Sai Krishna Issue	01:15 Min	Breaking News	Abc	
19.06.2026	Sakshi TV	17:00	YSRCP MP's Meet With NHRC Chairman	01:01 Min	Breaking News	Abc	
19.06.2026	TV9 Bharatvarsh	13:30	YCP MPs Meet NHRC Over Sai Krishna & Kranthi Kumar Cases -YSRCP MPs Maddila Gurumoorthy and Gumma Tanuja Rani met with the National Human Rights Commission (NHRC) in New Delhi. The delegation submitted a formal complaint demanding a thorough central investigation into the controversial Gade Sai Krishna case and the tragic suicide of Kranthi Kumar in Vijayawada. The MPs raised serious allegations of human rights violations and police excesses, urging national authorities to intervene immediately to ensure justice for the families.	00:42 Min	Breaking News	Abc	
19.06.2026	V6 News	14:20	MP Gurumoorthy Files NHRC Complaint Over Saikrishna's Disappearance	00:53 Min	Breaking News	Abc	
19.06.2026	News State	10:20	Kasna Jail में नाबालिग को बड़े कैदियों के साथ रखने का मामला, Human Rights Commission ने लिया संज्ञान	01:42 Min	Breaking News	Prashant	
19.06.2026	News State	14:00	Kasna Jail में नाबालिग को बड़े कैदियों के साथ रखने का मामला, Human Rights Commission ने लिया संज्ञान	02:15 Min	Breaking News	Abc	

19.06.2026	Lallantop	---	'फुटपाथ पर चलना फंडामेंटल राइट', सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून बनाने को कहा एक अहम फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) के तहत सुरक्षित एक फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा कि पैदल चलने वालों के अधिकारों को मोटर गाड़ियों से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए और सरकारों और लोकल अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया कि वे सुरक्षित, साफ़ तौर पर तय फुटपाथ बनाएं और उनका रखरखाव करें। यह बात एक सड़क दुर्घटना मुआवज़े के मामले की सुनवाई के दौरान कही गई, जिसमें पांच साल के बच्चे की मौत हो गई थी। कोर्ट ने पैदल चलने वालों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की भी आलोचना की और पूरे देश में सुरक्षित पैदल चलने के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए एक अलग कानूनी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश की।	05:45 Min	Exclusive	Abc	
19.06.2026	Pratidin TV	17:30	Balianta Soumya mu*der Case -Soumya was beaten up, what if Dayal was suspended, my son got justice! Baliantha mob violence, Constable Soumya Ranjan Swain murder case: Chief Minister Mohan Charan Majhi has taken serious action! Government has suspended IPS officer Dayal Gangwar	24:48 Min	Breaking News	Abc	

19.06.2026	Aaj Tak	16:10	Supreme Court का अहम फैसला, 'फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार -सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना है. कोर्ट ने एक सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए फुटपाथों की सुरक्षा और निर्माण के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. अदालत ने कहा कि पैदल यात्रियों का अधिकार मोटर वाहनों से ऊपर है.	00:43 Min	Breaking News	Abc	
19.06.2026	OTV	18:00	Walking on safe footpaths is a fundamental right. Safe Footpaths Are a Fundamental Right, Rules Supreme Court -The Supreme Court has given this verdict. For this, the apex court has given importance to the construction of necessary infrastructure for pedestrians, demarcation and maintenance. The court has urged the government to bring a law that recognizes the municipal authorities and local bodies.	03:20 Min	Breaking News	Abc	